



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 वैशाख, 1938 (श०)

संख्या 498 राँची, सोमवार,

16 मई, 2016 (ई०)

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

10 मई, 2016

1. उपायुक्त, चतरा का पत्रांक-1369, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007
2. उपायुक्त, गोड्डा का पत्रांक-357/जि०स्था०, दिनांक 29 मई, 2010
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-9704, दिनांक 05 नवम्बर, 2015

संख्या-5/आरोप-1-18/2015 का.- 3790--श्री राजबल्लभ सिंह, सेवानिवृत्त झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-429/03, गृह जिला-पटना), पता- मो0-शिवपुरी, राधाकृष्ण मंदिर मार्ग, पो0+थाना-शास्त्री नगर, जिला- पटना, पिन-800023 के विरुद्ध इनके विभिन्न पदस्थापनों से संबंधित आरोपों एवं इस संबंध में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण निम्नवत् हैं:-

आरोप सं०-1-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप-

श्री विजय राम, पे०-अर्जुन राम, मेन रोड, चतरा, थाना+जिला-चतरा के द्वारा निगरानी ब्यूरो मुख्यालय में दिये गये लिखित प्रतिवेदन, जिसमें श्री राजबल्लभ सिंह, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चतरा के विरुद्ध 1000/- (एक हजार) रुपये घूस दाखिल खारिज रसीद काटने हेतु माँग की गयी। इसके आलोक में दिनांक 24 अगस्त, 2001 को कांड के प्राथमिकी अभियुक्त श्री सिंह के विरुद्ध कार्रवाई कर इनको रंगे हाथों 1000/- (एक हजार) रुपये रिश्त के तौर पर लिये निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

वादी श्री विजय राम द्वारा चतरा थाना अन्तर्गत टीकर पंचायत में खाता नं०-47, प्लॉट नं०-642, रकबा-0.08 डी० जमीन खरीदा गया था, जिसकी दाखिल खारिज केस नं०-103/96-97 द्वारा नामांतरण किया गया। वर्ष 96-97 एवं 97-98 में रसीद भी कटी, लेकिन वर्ष 98-99 से रसीद कटना अंचल कार्यालय द्वारा बंद कर दिया गया। अंचलाधिकारी श्री सिंह द्वारा आगे की रसदी काटने हेतु 5,000/- (पाँच हजार) रुपये की माँग की गयी। अंततः बात 2,000/- रुपये में तय हुई, जो दो किस्तों में एक-एक हजार करके देना था। वादी के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में निगरानी ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें सत्यापनकर्ता श्री दिवाशंकर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक, निगरानी ब्यूरो ने 2,000/- रुपये रिश्त की माँग को सत्य पाया। सत्यापन के उपरांत निगरानी ब्यूरो के वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार श्री सिंह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चतरा के विरुद्ध निगरानी थाना, राँची कांड सं०-12/2001, दिनांक 23 अगस्त, 2001 धारा-7/13 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 दर्ज किया गया।

निगरानी ब्यूरो धावा दल द्वारा उपलब्ध कराये गये जी०सी० नोटों का मेमोरेण्डम बनाया गया, जिसमें नोटों के नम्बर का उल्लेख किया गया। जैसे ही श्री सिंह ने वादी से रिश्त के तौर पर पाउंडर लगे नोटों को लिया एवं अपने कुरता में रखा, निगरानी धावा

दल ने श्री सिंह को पकड़ लिया। इस प्रकार श्री सिंह के विरुद्ध धारा-7/13 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया गया।

आरोप सं0-2- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शालीग्राम, रामनारायणपुर, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-1369, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्न आरोप लगाये गये हैं-

(i) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-307/05-06 शीला देवी, पति श्री गुलाईत सिंह, ग्राम बहेरी पंचायत कोबना का एक यूनिट इंदिरा आवास निर्माण के जांच के क्रम में पाया गया कि अयोग्य लाभुक का चयन किया गया है, जबकि लाभुक सुखी संपन्न व्यक्ति है। यह मार्गदर्शिका का उल्लंघन के साथ सरकारी राशि का दुरुपयोग का मामला बनता है।

(ii) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-485/05-06 सुदेश्वर ठाकुर, ग्राम कोबना का इंदिरा आवास निर्माण। लाभुक के बयान के अनुसार बिचैलिया द्वारा अवैध राशि 6000.00 रु० वसूल की गयी है। इस प्रकार उक्त आवास योजना निर्माण में बिचैलिया की सहभागिता पाई गई है। यह सीधे रूप से मार्गदर्शिका के उल्लंघन के साथ सरकारी राशि का दुरुपयोग का प्रकरण बनता है।

(iii) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-1203/05-06 मो० मोबिन अहमद का इंदिरा आवास निर्माण के जाँच के क्रम में अभिलेख में संलग्न फोटोग्राफ जाली पाया गया, स्पष्ट है कि जाली फोटोग्राफ लगाकर फर्जी निकासी की गई है, जो धोखाधड़ी का मामला बनता है।

(iv) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-384/05-06 वकील भुईया, पिता-श्री चुन्नी भुईया, ग्राम नावाडीह का इंदिरा आवास निर्माण के जांच के क्रम में अभिलेख में संलग्न फोटोग्राफ जाली पाया गया, स्पष्ट है कि यह धोखाधड़ी का मामला है।

(v) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-408/05-06 साबित्री देवी पति कुवंर रविदास ग्राम बांकी का इंदिरा आवास निर्माण। अभिलेख में संलग्न फोटो जाली पाया गया। यह धोखाधड़ी एवं वित्तीय गबन का मामला बनता है।

(vi) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-374/05-06 सहोदरी देवी, पति-दिलेश यादव, ग्राम-गढ़ केदली का इंदिरा आवास निर्माण। जाँच के क्रम में योजना में प्लास्टर कार्य नहीं किया हुआ पाया गया, जबकि योजना अभिलेख में संलग्न फोटो में प्लास्टर किया हुआ है, जो जाली है। यह धोखाधड़ी एवं वित्तीय गबन का मामला बनता है।

(vii) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-07/06-07, श्री राजदेव मिस्त्री, ग्राम-केदली कला का इंदिरा आवास निर्माण। जाँच के क्रम में पाया गया कि लाभुक का चयन गलत ढंग से किया गया है। अभिलेख में लाभुक को तीन किस्त राशि भुगतान दिखाया गया है, जबकि लाभुक द्वारा तृतीय किस्त की राशि मो0 8070.00 रु0 भुगतान नहीं लेने की लिखित शिकायत की गयी है। इस प्रकार प्रथम द्रष्टव्य सभी संबंधित की मिलीभगत से जालसाजी कर सरकारी राशि की निकासी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से हुआ है, प्रतीत होती है।

(viii) इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता- योजना सं0-720/05-06, 623/05-06, 606/05-06, 151/06-07, 159/06-07, 150/06-07, 149/06-07, 132/06-07, 874/06-07 के अभिलेख में तथाकथित लाभुक एवं आवास के जाली फोटोग्राफ के आधार पर राशि की निकासी की गयी है।

(ix) दीनदयाल आवास योजना के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता- दिनांक 25 अक्टूबर, 2007 को शालीग्राम रामनारायणपुर प्रखण्ड कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दीनदयाल आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत/क्रियान्वित 193 एवं 06-07 की 118 कुल-311 योजनाएँ अपूर्ण पाई गई है। योजनाओं की पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के डेढ़/दो वर्ष से ऊपर होने पर भी

योजनाएँ भौतिक रूप से अपूर्ण हैं परंतु अधिकतर का पूर्ण होने विषयक प्रतिवेदन पहले भेजा गया है, जो वित्तीय अनियमितता/सरकारी कार्यों में लापरवाही/शिथिलता/मनमानेपन, कार्य में उदासीनता एवं फर्जी रिपोर्ट का परिचायक है।

(x) मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को जोरी में हुई साम्प्रदायिक तनाव की घटना, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य सभी वरीय पदाधिकारी पूरी रात उपस्थित थे, में स्थल पर पूरी रात अनुपस्थित रहे एवं इस अवधि में उनसे सम्पर्क करने के प्रयास में पाया गया कि ये अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से गायब हैं एवं मोबाईल भी ऑफ है। स्पष्टतः यह सेवा संहिता के प्रतिकूल सरकारी कर्मचारी के आचरण का परिचायक है।

(xi) सक्षम पदाधिकारी के बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहना- दिनांक 15 नवम्बर, 2007 से 18 नवम्बर, 2007 तक का राजपत्रित अवकाश अवधि में मुख्यालय छोड़ने संबंधी आवेदन पर बिना वरीय पदाधिकारी से स्वीकृति लिये श्री सिंह, प्र०वि०पदा० द्वारा मुख्यालय छोड़ा गया। तत्पश्चात आरोप गठन की तिथि तक बिना किसी अनुमति से अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित है, फलस्वरूप प्रखण्ड का विकास कार्य पूर्ण रूप से बाधित है, जो सेवा संहिता के प्रतिकूल है।

(xii) नरेगा के तहत क्रियान्वयन योजना अनियमितता- योजना सं०-22/06-07, ग्राम-हिरिंग में 153 चैनल से नौकाडीह तक हार्डसर्फेस पथ निर्माण में लाभुक समिति को किए गए भुगतान एवं मापी के अनुरूप कार्य नहीं पाया गया। स्थल पर पथ के किनारे अत्यन्त निम्नप्रकार का पत्थर गिरा हुआ पाया गया। पथ की लंबाई 2.00 कि० मी० के विरुद्ध मात्र 1.00 कि०मी० में मोरम बिछाई कार्य हुआ था एवं वह सभी प्राक्कलन के अनुरूप नहीं था। योजना में भौतिक सत्यापन किए बिना ही वास्तविक कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया। जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। योजना ससमय पूर्ण कराने की दिशा में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। योजना स्थल पर सूचना पट नहीं पाया गया, जो दिए गए निदेश का उल्लंघन है।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, शालीग्राम रामनारायणपुर के रूप में श्री राजबल्लभ सिंह इसके लिए सीधे रूप से जिम्मेदार है।

(xiii) नरेगा के तहत क्रियान्वयन योजना अनियमितता- योजना सं0-34/06-07, ग्राम-बलनिया में मनोज सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय तक हार्डसर्फेस पथ निर्माण में प्रथम अग्रिम 7500.00 रु० भुगतान के पश्चात् अबतक लंबित है। बिना कार्य कराये कनीय अभियंता के द्वारा 148666.00 रु० की मापी दर्ज की गयी है। योजना का ससमय पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा कनीय अभियंता द्वारा गलत मापी की सूचना उच्चाधिकारी को नहीं दी गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि कनीय अभियंता की मिलीभगत से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा गलत मापी के आधार पर सरकारी राशि निकालने का प्रयास किया गया है। योजना स्थल पर सूचना पट नहीं पाया गया, जो दिए गए निदेश का उल्लंघन है।

(xiv) नरेगा के तहत क्रियान्वयन योजना अनियमितता- योजना सं0-32/06-07, ग्राम-बलनिया में धुजा चौधरी के घर से बरवाही तक हार्डसर्फेस पथ निर्माण में लाभुक समिति को 397500.00 रु० का भुगतान किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि भुगतेय व मापी की राशि के विरुद्ध योजना कार्य नगण्य है। योजना ससमय पूर्ण नहीं कराने एवं गलत भुगतान के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिम्मेदार बनते हैं। योजना स्थल पर सूचना पट नहीं पाया गया, जो दिए गए निदेश का उल्लंघन है।

(xv) नरेगा के तहत क्रियान्वयन योजना अनियमितता- ग्राम-कटैया में महेन्दी टांड दस कटवा होते हुए कन्दवार सीमाना में लखपति भुईया के घर तक हार्डसर्फेस पथ निर्माण में जांच के क्रम में पाया गया कि लगभग 500 मीटर में मेटल/मोरम डाला गया है। मापी के अनुसार कार्य नगण्य पाया गया है। अभिलेख में मस्टर रॉल संलग्न नहीं था। नरेगा में मस्टर रॉल एक वैधानिक दस्तावेज है और कई निदेश के बावजूद इसका अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है। योजना स्थल पर सूचना पट नहीं पाया गया, जो दिए गए निदेश का उल्लंघन है।

आरोप सं0-3-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहरमा, गोड्डा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-357/जि0स्था0, दिनांक 29 मई, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

(i) श्री राजबल्लभ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा दिनांक- 3 मई, 2010 को अपने छोटे पुत्र का कार दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण पुत्र के ईलाज हेतु दिनांक 10 मई, 2010 तक का अवकाश में रहने संबंधी आवेदन पत्र भेजकर बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित है। श्री सिंह दिनांक 11 मई, 2010 को अवकाश से वापस मुख्यालय नहीं लौटे। अवकाश से न लौटने के कारण इस कार्यालय के वेतार संवाद संख्या-307/स्था0 दिनांक-11 मई, 2010 द्वारा श्री सिंह को आगे लंबे अवकाश में रहने की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा का प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोआरीजोर को सौंपने का निदेश दिया गया था। परन्तु इनके द्वारा न तो अवकाश से वापस लौटकर योगदान ही किया गया और न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा का प्रभार ही सौंपा गया। बल्कि श्री सिंह ने दिनांक- 15 मई, 2010 को फैक्स के माध्यम से एक आवेदन पत्र भेजते हुए इन्होंने दिनांक-11 मई, 2010 से दिनांक 30 मई, 2010 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किये। उनके द्वारा उपार्जित अवकाश आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है। श्री सिंह के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण प्रखंड मेहरमा में चल रहे मनरेगा/बी०आर०जी०एफ० योजनाओं आदि अन्य विकास योजनाओं की प्रगति बिल्कुल ही असंतोषप्रद है। श्री सिंह के अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण मेहरमा प्रखंड के मनरेगा आदि अन्य विकास की योजना जैसे अतिमहत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन लगभग बंद हो जाने एवं आम जनता के कठिनाईयों के मद्देनजर प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा का प्रभार स्थानीय व्यवस्था के तहत श्री धीरेन्द्र नारायण, सहायक परियोजना पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए०, गोड्डा को एवं अंचलाधिकारी, मेहरमा का प्रभार श्रीमती लीली

एनोला लकड़ा, अंचलाधिकारी, बोआरीजोर को ग्रहण कर कार्य करने का आदेश निर्गत किया गया है।

(ii) श्री सिंह प्रायः मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, विकास एवं योजना संबंधी कार्य में भी इनके द्वारा लापरवाही बरती जाती है। मनरेगा योजना में इनके द्वारा बहुत कम मात्र 37% प्रतिशत राशि योजना मद में व्यय किया गया है। मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में श्री राजबल्लभ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मेहरमा द्वारा प्राप्त उपलब्धि प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मेहरमा प्रखंड में पर्याप्त राशि उपलब्ध रहने के बावजूद भी अन्य प्रखंडों के तुलनात्मक सबसे कम व्यय किया गया है। इस जिले में मनरेगा अन्तर्गत सबसे कम व्यय की उपलब्धता के लिये श्री राजबल्लभ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मेहरमा को इस कार्यालय के पत्रांक 458/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 27 अप्रैल, 2010 से कारण पृच्छा की माँग की गई थी, जो अभी तक अप्राप्त है। यह उनके सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है। अन्य प्रखंडों की अपेक्षा व्यय कम होने के संबंध में श्री सिंह को अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 512/दिनांक 8 मई, 2010 द्वारा समुचित व्यय करने का निदेश दिया गया था।

(iii) इंदिरा आवास जैसी जनोपयोगी योजना के अन्तर्गत लाभूकों की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। दिनांक 19 जनवरी, 2010 को सम्पन्न जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के ज्ञापांक 296/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 19 फरवरी, 2010 से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि आगलगी परिवारों की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय, ताकि इंदिरा आवास योजनाओं की स्वीकृति दी जा सके। दिनांक 19 जनवरी, 2010 को सम्पन्न जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही, ज्ञापांक 296/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 19 फरवरी, 2010 के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक-177/वि०, दिनांक



26 फरवरी, 2010 द्वारा अग्निपीडित 40 लाभुकों की अधूरी सूची अभिकरण कार्यालय, गोड्डा को अनुमोदन हेतु भेजा, जिसमें सिर्फ नाम एवं पता अंकित था। सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राप्त सूची में आगजनी की घटना कब और किस वर्ष हुई है, घर पूर्ण या आंशिक जलने का प्रमाण पत्र, बी०पी०एल० नम्बर एवं स्कोर आदि नहीं रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-597/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 29 मार्च, 2010 द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन की माँग की गई थी। स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः स्पष्ट प्रतिवेदन मूल रूप से नियमानुसार अनुमोदन हेतु भेजने का निदेश इस कार्यालय के पत्रांक-721/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 22 अप्रैल, 2010 के द्वारा दिया गया था, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा द्वारा अपने पत्रांक-242/वि०, दिनांक 22 अप्रैल, 2010 से 40 अग्निपीडित लाभुकों के स्थान पर 55 अग्निपीडित लाभुकों की सूची अनुमोदन हेतु भेजा गया। उनसे अनुमोदन हेतु प्राप्त सूची त्रुटिपूर्ण रहने के कारण सूची अनुमोदन नहीं किया जा सका। उन्हें पुनः त्रुटियों का निराकरण कर अग्निपीडित लाभुकों की सूची अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के साथ अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-742/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 26 अप्रैल, 2010 द्वारा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा को अनेकों बार व्यक्तिगत रूप से कहने के बावजूद उनके द्वारा अपने पत्रांक-255/वि०, दिनांक 28 अप्रैल, 2010 द्वारा 55 अग्निपीडित लाभुकों की सूची अनुमोदन हेतु अभिकरण कार्यालय, गोड्डा को भेजा गया। उक्त सूची में भी कुछ त्रुटियाँ पायी गयीं। प्राप्त सूची में से मात्र 40 अग्निपीडित लाभुकों की सूची अनुमोदनोपरांत इस कार्यालय के पत्रांक- 755/डी०आर०डी०ए०, गोड्डा दिनांक 30 अप्रैल, 2010 द्वारा उन्हें वापस किया गया। ज्ञातव्य हो कि श्री राजबल्लभ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा ही अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रभार में थे, परन्तु उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना ढंग से सूची भेजा जाता रहा और अग्निपीडित लाभुकों को इंदिरा आवास योजना स्वीकृत करने में लगभग दो माह लग गया। 40 अग्निपीडित लाभुकों की सूची अनुमोदनोपरांत लाभुकों को भुगतान हेतु पूरी राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा को उपलब्ध कराने के बावजूद भी उनके द्वारा लाभुकों को

प्रथम किस्त की सभी राशि का भुगतान अबतक नहीं किया गया है। फलस्वरूप लाभुकों द्वारा अभी तक आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा जानबूझ कर सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। उनके कार्यकलाप के कारण मेहरमा प्रखंड की उपलब्धि असंतोषजनक रही है। ज्ञातव्य हो कि अग्निपीडित लाभुकों को इंदिरा आवास स्वीकृत करने के संबंध में माक्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, मेहरमा के द्वारा मेहरमा प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्य किया गया था। परन्तु उनके द्वारा अपने कार्यकलाप को छुपाने हेतु गलत प्रतिवेदन अपने पत्रांक-239/दिनांक 17 अप्रैल, 2010 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को समर्पित किया। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा सरकारी कार्यों में घोर लापरवाही, उदासीनता बरतने एवं गलत प्रतिवेदन देकर कार्यकलाप को छुपाने का प्रयास किया गया।

(iv) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखंड/अंचल कार्यालय, मेहरमा के औचक निरीक्षण में पाया गया कि प्रखंड नजारत एवं अंचल नजारत के रोकड़ पंजी का संधारण भी इनके द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रखंड नाजीर द्वारा रोकड़ बही का संधारण एवं आय-व्यय का इन्द्राज 28 फरवरी 2010 तक ही किया गया है। रोकड़ बही का अद्यतन संधारण न करने के आरोप में प्रखंड कार्यालय, मेहरमा के प्रधान लिपिक एवं प्रखंड नाजीर को जिला स्थापना शाखा, गोड्डा के आदेश ज्ञापांक-336/स्था0, दिनांक 20 मई, 2010 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रखंड नजारत एवं अंचल नजारत के रोकड़ पंजियों की जाँच हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोड्डा के अध्यक्षता में एक टीम गठित कर रोकड़ पंजियों की जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा अधिकांश रोकड़ पंजी माह दिसम्बर 2009 से फरवरी 2010 तक अद्यतन कर हस्ताक्षरित किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा लगभग ढाई माह से रोकड़ पुस्त संधारण नहीं किया गया है, जो कोषागार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। रोकड़ पुस्त संधारित नहीं किये जाने के कारण वित्तीय

अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो प्रथम दृष्ट्या विभागीय अनियमितता का मामला दृष्टिगत होता है।

(v) श्री सिंह स्थानीय व्यवस्था के तहत अंचलाधिकारी, मेहरमा के भी प्रभार में है। अनधिकृत अनुपस्थिति के वजह से अंचल कार्यालय से निर्गत होने वाले विभिन्न प्रकार के यथा-आय, जाति, निवासी प्रमाण पत्रों को ससमय निर्गत नहीं किये जाने की स्थिति में आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है। मुख्यालय में उपस्थित न रहने के कारण राजस्व संबंधी कार्य की प्रगति भी अवरूद्ध है राज्य/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशनधारियों की राशि विगत सात माह से पेंशन का भुगतान लाभुकों के बीच नहीं किया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक-244/स्था0, दिनांक 17 अप्रैल, 2010 द्वारा श्री सिंह से पत्र प्राप्ति के साथ स्पष्टीकरण की माँग की गई थी। परन्तु इनके द्वारा अभी तक स्पष्टीकरण का जवाब अप्राप्त है।

(vi) श्री राजबल्लभ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, मेहरमा को उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता, सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता एवं अनधिकृत अनुपस्थित रहने के आरोप में इन्हें प्रशासनिक दृष्टिकोण से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है।

#### आरोप सं०-4-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग के पदस्थापन काल में स्थानीय विधायक माननीय श्री योगेन्द्र साव द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध माननीय श्री सुबोध कांत सहाय, तत्कालीन केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार को परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं-

1. दिनांक 4 फरवरी, 2011 को मैं टंडवा लीग टूर्नामेंट, जहाँ मैं मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित था, से लौट रहा था। लौटने के क्रम में केरेडारी चैक में मैंने देखा की वहाँ की जनता केरेडारी बी0डी0ओ0 राजबल्लभ सिंह को घेरे हुई थी और विकास मद

में किए गए कार्यों हेतु चेक निर्गत करने के मामले पर जगेश्वर साव और खिरोधर साव से बी०डी०ओ० द्वारा चेक निर्गत करने के एवज में 10,000/- रुपये और बतौर घूस माँगने को लेकर विवाद हो रहा था। ज्ञात हो कि इस काम के लिए इन दोनों व्यक्तियों से बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह ने पहले ही 10,000/- रुपया लिया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो जनता बी०डी०ओ० के साथ धक्का-मुक्की कर रही थी। यह देखते हुए मैं भीड़ से बचा कर बी०डी०ओ० को केरेडारी थाना ले गया और थानेदार से भुक्तभोगी दोनों युवक जगेश्वर साव और खिरोधर साव के द्वारा बी०डी०ओ० के विरुद्ध F.I.R. करने की बात कर कर वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र के और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। मुझे रात में यह जानकारी मिली की S.D.O. विनय कुमार राय जो बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह के रिश्तेदार है, के दवाब में इस वाक्य में उलटे पीड़ित व्यक्तियों पर ही F.I.R. कर दिया गया है और जानबूझ कर मेरा नाम भी F.I.R. में शामिल कर दिया गया है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मैंने बी०डी०ओ० के साथ कोई मारपीट नहीं की मगर स्थानीय प्रशासन ने बी०डी०ओ० और एस०डी०ओ० के दबाव में आकर यह कारनामा कर दिया और जनता और जन प्रतिनिधि का साथ न देकर भ्रष्ट अधिकारियों के तलवे चाटते दिखी। राजबल्लभ सिंह के कई कारनामों पहले भी उजागर हो चुके हैं।

2. राजबल्लभ सिंह काफी चर्चित अधिकारी रहे हैं। चतरा कॉलेज की एक छात्रा की लिखित रिपोर्ट पर चतरा सदर थाना में बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह के खिलाफ 30 जून, 2001 को छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। छेड़खानी के इस मुकदमें में जमानत का दुरुपयोग करने के कारण श्री सिंह के खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारंट भी जारी किया गया लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। राँची से प्रकाशित एक प्रमुख दैनिक में इस संवाददाता द्वारा लिखी गई रिपोर्ट के बाद श्री सिंह द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। जहाँ उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।

3. 24 अगस्त, 2001 को बी०डी०ओ० श्री सिंह चतरा स्थित अपने निवास स्थान पर घूस लेते हुए निगरानी विभाग द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए।

19 सितम्बर 2001 को उनकी नियमित जमानत याचिका निगरानी विभाग के विशेष न्यायाधीश डी० के० लाल की अदालत द्वारा खारिज कर दी गयी।

4. सिटिजन कॉलेज की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को दागी अफसरों की सूची पेश करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए उन्हें 12 अक्टूबर 2004 तक का समय दिया गया। 12 अक्टूबर को एक शपथ पत्र के द्वारा सरकार द्वारा 363 दागी अधिकारियों की सूची हाईकोर्ट में दाखिल की गई। बताया जाता है कि इस सूची में बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह का भी नाम है।

5. अप्रैल 2006 में चतरा उपायुक्त शत्रुधन प्रसाद कुवर ने सिमरिया प्रखण्ड के कनीय अभियंता अवधेश कुमार सिंह पर गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया गया। कनीय अभियंता पर सिमरिया प्रखण्ड के डाडी गाँव में बगैर तालाब का निर्माण कराये योजना पद की सभी राशि निकालने का आरोप था। सिमरिया के बी०डी०ओ० रहते हुए राजबल्लभ सिंह द्वारा बगैर स्थल निरीक्षण किए हुए इसका भुगतान कर दिया था। यह तालाब राष्ट्रीय सम विकास योजना से निर्माण होना था। राजबल्लभ सिंह के कार्यकाल में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सिमरिया प्रखण्ड के जागी पंचायत के चैराही गाँव में बिना सड़क एवं कुआँ बनवाये आधे से अधिक की राशि निकाल ली गयी।

6. वन विभाग द्वारा भी लावालोंग के प्रभारी बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह पर अवैध उत्खन्न का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया।

7. हंटरगंज प्रखण्ड में इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितता की शिकायत की जाँच के बाद अक्टूबर 2007 में उपायुक्त पूजा सिंघल पुरवार ने बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' भरते हुए ग्रामीण विकास विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा की। बताया जाता है कि प्रखण्ड के कोबना पंचायत में वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में एक सौ से अधिक इन्दिरा आवास का निर्माण स्थल पर हुआ भी नहीं और राशि की निकासी कर ली गयी।

8. नरेगा योजना में जे०सी०बी० से काम करा रहे ठेकेदार को मशीन पुलिस द्वारा जप्त कर ली गयी। बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह की जाँच रिपोर्ट के बाद पुलिस उक्त जप्त मशीन को छोड़ने के लिए बाध्य हो गयी।

9. धनबाद जिला में पदस्थापित बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह का धनबाद उपायुक्त कोपभाजन का भी शिकार होना पड़ा। उपायुक्त ने श्री सिंह के खिलाफ अनियमितता की रिपोर्ट सरकार को भेजते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया।

10. विकास कार्य की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री मधुकोड़ा द्वारा बी०डी०ओ० राजबल्लभ सिंह को निलंबित करते हुए बैठक में उपस्थित चतरा उपायुक्त को श्री सिंह पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। उनपर एक ही परिवार की तस्वीरे चिपका कर तीन सौ इन्दिरा आवास इकाईयों का आरोपी पाये जाने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह आदेश दिया गया था।

11. बलियापुर थाना कांड संख्या-88/09, दिनांक 15 मार्च, 2009 के अनुसंधान के क्रम में भी राजबल्लभ सिंह का नाम अप्राथमिकी अभियुक्तों की सूची में आया है।

12. इन सब में सबसे नवीन कम्प्लेन केस सं०-143/11 है, जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग की अदालत में दिनांक 05 फरवरी, 2011 को दर्ज किया गया है, जिसमें राजबल्लभ सिंह पर 5000 रुपये लेने का आरोप विनोद राम द्वारा लगाया गया है। यह मामला हरिजन उत्पीड़न से जुड़ा है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-9704, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा श्री सिंह से समेकित रूप से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्री सिंह द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

आरोप सं0-1 पर स्पष्टीकरण-

श्री सिंह का कहना है कि चतरा जिला अन्तर्गत सदर प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे। तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा अतिरिक्त प्रभार अंचलाधिकारी, चतरा सदर का दिया गया है। श्री विजय राम, पे०- अर्जुन राम द्वारा इनके विरुद्ध निगरानी विभाग के द्वारा उपस्थित लोगों के समक्ष बलपूर्वक गला दबाकर पकड़ा गया। इस संबंध में इन्होंने सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया। इन्होंने उल्लेख किया है कि तत्कालीन उपायुक्त ने श्री अर्जुन राम के द्वारा किये गये गैर मजरूआ भूमि के अतिक्रमण के संबंध में पूर्व के अंचलाधिकारी पर भी किये गये आरोप पर विस्तृत प्रतिवेदन सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को समर्पित किया गया था। उपायुक्त महोदय के मंतव्य पर माननीय सचिव द्वारा महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से मंतव्य की माँग की गयी थी।

इनका कहना है कि निगरानी विभाग द्वारा गृह तलाशी के क्रम में पाये गये वेतन राशि को माननीय न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया तथा एक षडयंत्र के तहत इन्हें फंसाया गया था, लगाये गये आरोप से मुक्त करने का अनुरोध इनके द्वारा किया गया है।

आरोप सं0-2 पर स्पष्टीकरण-

चतरा जिला अन्तर्गत शालीग्राम, रामनारायणपुर (हंटरगंज) प्रखण्ड में दिनांक 14 जुलाई, 2006 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण किया गया था।

इनका कहना है कि इंदिरा आवास के भुगतान में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में इनका कहना है कि प्रायः अधिकांश योजना प्रभार लेने के पूर्व का है। इंदिरा आवास का स्थल जाँच पंचायत सेवक और कनीय अभियंता द्वारा

मकान के सामने लाभुक के साथ स्थल फोटो दो प्रतियों में प्राप्त होता था, एक प्रति संबंधित लाभुक के अभिलेख में और एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त होता था, फोटो के पीछे लाभुक और पंचायत सेवक का हस्ताक्षर होता था। अभिलेख में रखे फोटो को उपायुक्त महोदया (श्रीमती पुजा सिंघल) के निरीक्षण के एक दिन पूर्व अभिलेख से फोटो हटाकर दूसरा फोटो लाभुक के अभिलेख में एक षडयंत्र के तहत रखकर इन्हें फंसाया गया था। इस संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन मा० मुख्यमंत्री, आरक्षी अधीक्षक, चतरा, आरक्षी महानिदेशक, राँची एवं सचिव, गृह विभाग को लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

इनके आवेदन पर गृह विभाग के पत्रांक-43, दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 के द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग से जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के आलोक में लगाया गया आरोप को स्थगित कर दिया गया।

इनके आँख के रौशनी खराब हो रहा था, तो इन्होंने अमृतसर अस्पताल जाकर विशेषज्ञ चिकित्सक से जाँच कराने के पूर्व तत्कालीन उपायुक्त महोदया से मिलकर आवेदन दिया गया था। उपायुक्त, महोदया द्वारा अनुमति भी दी गयी थी। अतः लगाये गये आरोप से नम्रतापूर्वक मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

#### आरोप सं०-3 पर स्पष्टीकरण-

गोड्डा जिला अन्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड में दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण किया गया था। तत्कालीन उपायुक्त द्वारा अंचलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, मेहरमा अंचल से अग्निपीडित लाभुकों की सूची की माँग पर अंचल के पत्रांक-255, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया।

इनका कहना है कि इनके पुत्र श्री सुमित कुमार मुम्बई में कार दुर्घटना के कारण जीवन से जुझ रहे थे। श्री सिंह को रात्रि करीब 02:30 बजे में मोबाईल पर



सूचना मिली। तत्पश्चात् इन्होंने उपायुक्त महोदय को रात्रि 03:30 बजे SMS किया था। साथ ही, सुबह 05:00 बजे प्रस्थान करते समय मोबाईल पर भी वार्ता हुई और उपायुक्त द्वारा अनुमति भी दिया गया था। साथ ही, वार्तानुसार आवेदन भी भेज दिया गया था। उन्होंने उल्लेख किया है कि मुम्बई में सर्वप्रथम सूर्या अस्पताल से स्थानांतरित कर हिन्दुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनके कार्य के संबंध में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। इनके पुत्र की ऐसी स्थिति को देखते हुए लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

#### आरोप सं0-4 पर स्पष्टीकरण-

1. इनका कहना है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत केरेडारी प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में दिनांक 03 सितम्बर, 2010 को प्रभार ग्रहण किया था। दिनांक 04 फरवरी, 2011 को हेवई पंचायत में ग्राम सभा और जोरदाग पंचायत में राजस्व शिविर था। प्रखण्ड कार्यालय से सरकारी वाहन से केरेडारी चैक पर पहुँचते हुए तत्कालीन विधायक श्री योगेन्द्र साव विपरीत दिशा में रोक कर इन्हें गाड़ी से बुलाकर गाली गलोज करते हुए कहने लगे कि श्री योगेश्वर साव, खिरोधर साव, के योजना में किये गये कार्य का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्थल जाँच में पाया गया कि स्थल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कनीय अभियंता का नापी और M/R गलत है। इसके बाद इन्हें विधायक और श्री योगेश्वर साव, खिरोधर साव और अन्य के द्वारा मिलकर लात मुक्का से मारने लगे और भीड़ जुटने के पश्चात् कुछ लोग किसी तरह से जान बचाकर इन्हें थाना ले गये। वहाँ पर वस्तुस्थिति से लिखित प्रतिवेदन थाना प्रभारी, केरेडारी को कानूनी कार्रवाई हेतु दिया, एम्बुलेंस के द्वारा हजारीबाग अस्पताल में भरती कराया गया। श्री सिंह द्वारा अवकाश लेकर पटना के विशेषज्ञ चिकित्सक से जाँच कराया।

2. श्री सिंह का कहना है कि धनबाद जिला अन्तर्गत बलियापुर प्रखण्ड में दिनांक 08 जनवरी, 2008 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण किया गया था। लगाये गये सभी आरोपों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज

(Quashed) कर दिया गया है। अतः लगाये गये सभी आरोपों से मा० उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आरोप मुक्त करने का अनुरोध श्री सिंह द्वारा किया गया है।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समेकित रूप से समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

आरोप सं०-2 में श्री सिंह के विरुद्ध नरेगा योजनाओं में नियमित पर्यवेक्षण एवं स्थल निरीक्षण किये बिना गलत मापी के आधार पर भुगतान करने, इंदिरा आवास योजना एवं दीन दयाल आवास योजना में जाली फोटोग्राफ के आधार पर राशि की निकासी करने तथा दिनांक 18 सितम्बर, 2007 को जोरी में हुई साम्प्रदायिक तनाव की घटना के समय अनाधिकृत अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित होता है।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 139(ख) के तहत 10(दस) प्रतिशत पेंशन की राशि कटौती करने का दण्ड दिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव।

-----